प्रभात खबर
www.prabhatkhabar.com

प्रशासनिक सुधार के लिए 'सुशासन केंद्र'

पटना : राज्य सरकार ने सूबे में प्रशासनिक सुधार के उद्देश्य से सुशासन का केंद्र की स्थापना की है. इसके लिए सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी का गठन किया गया है. इसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे. सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को गठन से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है.

अधिसूचना जारी

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि प्रशासनिक सुधार/ प्रशासनिक तंत्र की बिहार में मजबूती के लिए सतत परामर्श एवं बौद्धिक विकास के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों की विचारक संस्था में रूप में यह संस्था काम करेगी.

नव निर्माण के दृष्टिकोण से प्रशासन की सवरेत्तम व्यवस्था, प्रशासन एवं सेवा प्रदान करने की व्यवस्था पर शोध एवं उपलब्ध ज्ञान का प्रबंधन सोसाइटी करेगी. इसके अलावा नीति निर्धारण में भी सोसाइटी सहयोग देगा.

धरातल आधारित शासन एवं कार्य कुशल व उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था, गरीबों के विकास की योजना तैयार करने, नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने, महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रापण, सूत्रण एवं क्रियान्वयन की दिशा निर्धारण, आवश्यक आधारित पहचान के क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशासन के महत्वपूर्ण अव्यवों का क्षमता विकास करेगा.

भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभागों तथा अन्य स्वायत्त संस्थाओं से परियोजनाओं के लिए बाजार दर पर सलाहकार उपलब्ध करायेगा. सुशासन केंद्र सोसाइटी के शासी परिषद का गठन किया गया है.

मुख्य सचिव होंगे अध्यक्ष

मुख्य सचिव सोसाइटी के अध्यक्ष व विकास आयु उपाध्यक्ष होंगे. बिपार्ड के महानिदेशक, वित्त विभाग के प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव, ख्याति प्राप्त एकेडमिक इंस्टीटय़ूट के अध्यक्ष यथा भारतीय प्रबंधन संस्थान अथवा पटना स्थित विशिष्ट शैक्षणिक संस्थान को सदस्य बनाया गया है. सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी के महानिदेशक सदस्य सचिव होंगे.